

न्यूज़ इन शॉर्ट

उज्जैन के नफीस ने धर्म बदलने का दबाव बनाया, मामला दर्ज

विजय मत, ब्यूरो उज्जैन। उज्जैन में एक हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। मामला मंगलवार दोपहर का है। नफीस खान ने कानू पटेल बनकर एक युवती से सोशल मीडिया पर दोस्ती की और बातचीत करने लगा। कुछ समय बाद युवती को पता चला कि जिससे वह प्यार करती है, वह मुस्लिम है। इसके बाद उसने बातचीत बंद कर दी। तभी युवक ने युवती के परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देकर पार्क में मिलने बुलाया। यहां उसने कहा कि शादी करनी पड़ेगी और धर्म भी बदलना पड़ेगा। मना करने पर छेड़छाड़ शुरू कर दी। युवती ने शोर मचाया तो भीड़ जमा हो गई। कुछ देर में हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में थाने पहुंची युवती ने भी एफआईआर दर्ज कराई है।

लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार

न्यूज, एजेंसी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिकी बूम्बज द निर्णय से पहले सतर्कता के कारण बुधवार को बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बेंचमार्क सूचकांक संसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 138.64 अंक या 0.16 प्रतिशत गिरकर 81,444.66 अंक पर बंद हुआ।कमजोर शुरूआत के बाद सुबह के कारोबार में इंडेक्स 81,858.97 के उच्च स्तर पर पहुंच गया, लेकिन बाद में बढ़त बरकरार नहीं रख सका। सेंसेक्स 346.29 अंक या 0.42 प्रतिशत गिरकर 81,237.01 के निचले स्तर पर पहुंच गया। वहीं, एनएसई निफ्टी 41.35 अंक या 0.17 प्रतिशत गिरकर 24,812.05 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सबसे ज्यादा 1.79 प्रतिशत घाटे में रही।

केवाईसी एजेंसियों को मिलेगी मान्यता, निवेशकों को होगा लाभ

नई दिल्ली, एजेंसी। बाजार नियामक सेबी ने केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों (केआरए) के लिए बड़ा प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत केवाईसी एजेंसियों को अब मान्यता एजेंसी के रूप में काम करने की अनुमति दी जा सकती है। वर्तमान में यह सुविधा केवल स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी की सहायक कंपनियों तक ही सीमित है। सेबी ने इस प्रस्ताव पर 8 जुलाई तक आम जनता से सुझाव मांगें हैं। परामर्श पत्र में सेबी ने कहा कि मान्यता एजेंसियों के लिए पात्रता मानदंड को विस्तारित किया जा सकता है, ताकि सभी केआरए मान्यता एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए पात्र हों। वर्तमान में बाजार में सिर्फ दो मान्यता एजेंसियां काम कर रहीं हैं। सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड, जो सीडीएसएल की सहायक कंपनी है।

अब 15 दिन के भीतर घर पहुंचेगा मतदाता पहचान पत्र: ईसीआई

नई दिल्ली, एजेंसी। चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि उसने एक नई प्रक्रिया शुरू की है, जिससे मतदाता पहचान पत्र अब मतदाता सूची में अपडेट (नया नामांकन या किसी जानकारी में बदलाव) के 15 दिनों के भीतर मतदाता को भेज दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक मतदाता पहचान पत्र पहुंचने में एक महीने से ज्यादा का समय लग जाता है। आयोग ने कहा कि नई प्रणाली के तहत मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) बनने से लेकर डाक विभागके जरिए मतदाता तक पहुंचने तक हर चरण की रियल-टाइम ट्रैकिंग की जा सकेगी। यह प्रक्रिया निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा कार्ड जनरेट किए जाने के बाद से शुरू होगी। चुनाव निकाय ने बताया कि इसके साथ ही हर चरण में मतदाता को संदेश (एसएमएस) के जरिए जानकारी दी जाएगी।

मुझे मेरी बीवी से बचाओ... मुख्यमंत्री से लगाई गुहार, बोला- पत्नी अपने दो प्रेमियों से कराना चाहती है मेरा कत्ल

बहादुरगढ़, एजेसी सात फरवरी को पत्नी के साथ फेरों के बंधन में बंधने वाले पति को पांच माह में ही पत्नी के प्रेमी से हत्या का खतरा सताने लगा है। इस बीच एक बार उस पर जानलेवा हमला हो भी चुका है। ऐसे में अपनी पत्नी से जान बचाने को लेकर पीड़ित ने पंचायत से लेकर तमाम प्रयास करने के बाद अब अधिकारियों से सुरक्षा की मांग की है। मेरठ के जागृति विहार में रहने वाले एक युवक का विवाह इसी वर्ष सात फरवरी को स्थाना के बुरासी चौकी क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले एक गांव निवासी की बेटी से हुआ था। पीड़ित का आरोप है कि शादी के बाद से ही पत्नी का स्वभाव विपरित था। इसी कारण से अधिकांश समय पत्नी ने अलग बिताया। दो जून की रात वह गुरुग्राम से मेरठ आ रहा था। इस बीच एक बाइक पर सवार दो युवक उसका पीछा कर रहे थे। मुरादनगर नहर से मोदीनगर के बीच पहुंचने पर अचानक उन्होंने बाइक में लात मार दी, जिससे पीड़ित सड़क पर गिर गया। इस दौरान बाइक का नंबर नोट कर लिया गया था। नंबर के आधार पर जांच की गई तो पता चला कि वह बाइक सवार दोनों युवक उसकी पत्नी के प्रेमी थे। इस बात को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों को बताया कि तो गढ़ एवं स्थाना क्षेत्र के कुछ रिश्तेदारों को लेकर बहादुरगढ़ के डेहराकुटी स्थित एक स्कूल में पंचायत की गई। पंचायत में कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला।

ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने किया जंग का ऐलान, कहा- इस्राइल ने हमला कर बड़ी गलती की

ईरान कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा

तेहरान, एजेंसी

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा-जंग शुरू और हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे। अब कोई दया नहीं दिखाएंगे और इस ऐलान के बाद ईरान ने 25 मिसाइलें दागीं। ईरानी मीडिया के अनुसार इजराइल पर फतह मिसाइल से हमला किया है और यह पहली बार है जब इस जंग में फतह- 1 का इस्तेमाल किया है। फतह मिसाइल हाइपरसोनिक है, यानी यह आवाज की गति से 5 गुना तेज उड़ती है। फतह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया और बार-बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाने में सफल हुई है। अमेरिका इजराइल की रक्षा के लिए जमीन, समंदर और हवा से अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। आई आरजीसी ने कहा अब ईरान का इजराइल के आसमान पर कब्जा हो गया है। आई आरजीसी ने कहा कि फतह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। अब अमेरिका, इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले करेगा इसको लेकर ट्रम्प ने कोई फैसला नहीं लिया है। ट्रम्प को धमकी में हैं कि अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई की धमकी देता है तो ईरान बातचीत करेगा और अमेरिका की शर्तों को मान लेगा।

भारत से इजराइली हमलों की निंदा की उम्मीद: ईरान

वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ईरान से 'बिना शर्त आत्मसमर्पण' की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए खामेनेई ने कहा, 'जो लोग ईरान के इतिहास को जानते हैं, वे जानते हैं कि धमकी की भाषा ईरानी जनता के लिए कभी काम नहीं करती। अमेरिका को पता होना चाहिए कि किसी भी सैन्य कार्रवाई का अंजाम अपूरणीय नुकसान के रूप में होगा।'

ईरान अब बातचीत चाहता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है: डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि ईरान अब बातचीत करना चाहता है, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि- बातचीत के लिए बहुत देर हो चुकी है। इससे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा था कि ईरान आत्मसमर्पण नहीं करेगा।

तेहरान में फिर इजराइली हमला, धमाके के बाद चारों ओर फैला धुआं

ईरान की राजधानी तेहरान में फिर से इजराइली हमलों की खबरें हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेहरान के पूर्वी हिस्से में कई जगह धमाकों की आवाजें सुनी गईं और धुआं उठता देखा गया। इजराइल डिफेंस फोर्सने भी हमले की पुष्टि की है। तेहरान में ईरानी सरकार के सैन्य ठिकानों पर एयरक्राफ्ट के हमले जारी हैं। इजराइली प्रधानमंत्री बेनजामिन नेतन्याहू आज रात यरूशलेम में अपनी सुरक्षा केबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इसकी जानकारी वाइस ऑफ इजराइल ने एक कैबिनेट मंत्री के कार्यालय के हवाले से दी है।

कतर को भेजा गया विशेष संदेश

इस तनाव के बीच, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेरिस्तयान ने कतर के अमीर को एक गोपनीय पत्र भेजा है। हालांकि पत्र की सामग्री सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, परमाणु कूटनीति और इस्राइल-ईरान तनाव को लेकर बातें हो सकती हैं।

जायोनिस्टों के लिए कोई रहम नहीं: खामेनेई

बुधवार को एक्स पर खामेनेई ने लिखा, 'हमें आतंकवादी जायोनिस्ट शासन को जोरदार जवाब देना होगा। जायोनिस्टों के लिए कोई रहम नहीं होगी।' खामेनेई का यह बयान तब आया जब ईरान ने इस्राइल की बमबारी के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनमें ईरान के मुताबिक हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल हुआ।

चरण पादुका योजना: 21 को जशपुर से सीएम करेंगे शुभारंभ

अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक न्याय और सुविधा पहुंचाना ही सरकार की प्राथमिकता: साय

विजय मत, रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 21 जून को जशपुर जिले के तपकरा में चरण पादुका वितरण योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री इस मौके पर तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की महिलाओं को चरण पादुका वितरित करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने संकल्प पत्र में चरण पादुका योजना को फिर से शुरू किये जाने का वादा किया था।जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया था। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। यह योजना सीधे-सीधे राज्य के 12 लाख 40 हजार तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी। जिन्हें चरण पादुका का निःशुल्क

वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा हमारी सरकार की प्राथमिकता हमेशा अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक न्याय और सुविधा पहुंचाना है। तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों का राज्य की अर्थव्यवस्था और वनोपज आधारित आजीविका में अमूल्य योगदान है। चरण पादुका योजना हमारे संकल्प पत्र का वादा था, जिसे हम पूरा करने जा रहे हैं। यह सिर्फ चरण पादुका का वितरण नहीं, बल्कि संग्राहक परिवार के स्वाभिमान और सुरक्षा का प्रतीक है। सीएम ने आगे कहा- चरण पादुका वितरण योजना की शुरुआत इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ सरकार तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की आवश्यकता, सम्मान और गरिमा का ध्यान रख रही है।

रायपुर एयरपोर्ट: इंडिगो फ्लाइट का गेट लॉक, आधे घंटे फंसे रहे पूर्व सीएम, रायपुर मेयर सहित 35 यात्री

विजय मत, रायपुर

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट माना में उस समय खलबली मच गई, जब दिल्ली से रायपुर पहुंची फ्लाइट इंडिगो का गेट लॉक हो गया। इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। अफरार-तफररी जैसी स्थिति बन गई थी। करीब 40 मिनट तक गेट लॉक रहा। बड़ी बात ये रही कि इस फ्लाइट में प्रदेश के पूर्व सीएम

भूपेश बघेल, विधायक चातुरी नंद और रायपुर की मेयर मीनल चौबे समेत 35 से ज्यादा लोग इसमें बैठे हुए थे। मिली जानकारी के मुताबिक, तकनीकी वजहों से इंडिगो फ्लाइट का गेट लॉक हो गया था। 40 मिनट के बाद किसी तरह से गेट खुला और यात्रियों ने राहत की सांस ली। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यह फ्लाइट दिल्ली से रायपुर दोपहर 2.25 बजे पहुंची थी।

15 अगस्त से 3,000 रुपए के फास्टैग रिचार्ज से कर सकेंगे 200 ट्रिप

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि सरकार निजी वाहनों के लिए फास्टैग आधारित वार्षिक पास पेश करेगी, जिसकी कीमत 3,000 रुपये होगी। यह 15 अगस्त से प्रभावी होगा। यह राजमार्गों पर परेशानी मुक्त यात्रा की दिशा में एक कदम है। गडकरी ने कहा कि यह पास एक्टिवेशन की तारीख से एक साल या 200 ट्रिप तक, जो भी पहले हो, के लिए वैध है। यह पास खास तौर पर गैर-वार्गान्जिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए बनाया गया है।

छत्तीसगढ़ में जमीन गाइड लाइन की नई दर 1 जुलाई से होगी लागू, महंगी होगी प्रॉपर्टी

विजय मत, रायपुर

छत्तीसगढ़ में जमीन की कीमत जल्द ही बढ़ने वाली है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार 1 जुलाई से जमीन गाइड लाइन की नई दर लागू होने वाली है। इससे पहले पंजीयन विभाग ने प्रदेश के 33 जिलों में जमीन की प्रचलित दर का सर्वे पूरा कर लिया है। फिलहाल मूल्य का विश्लेषण जिलेवार और क्षेत्रवार किया जा रहा है। इस काम में पिछले कुछ महीनों में हुई देर की वजह से नई गाइड लाइन जारी करने में विलंब हुआ है। खास बात ये है कि राज्य में आठ साल बाद नई दरें लागू होने जा रहीं हैं। नई दरें आने से किसानों को सबसे अधिक फायदा होगा। दरअसल राज्य में सबसे अधिक जमीनें किसानों के पास ही है। किसी भी उपयोग के लिए सरकार द्वारा जो अभी जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है उसका मुआवजा मौजूदा गाइडलाइन दर पर होता है। जबकि किसानों की रोड से लगी जमीनों की असली कीमत गाइड लाइन से 10-15 गुना तक अधिक है। अब सरकार किसान की जमीन लेगी तो उसे भी नई दरों के हिसाब से मुआवजा देना होगा। जमीनों के सौदे के मामले में माना जाता है कि अधिकांश बड़ी टाउनशिप, कालोनियों के निर्माण के दौरान बिल्डर गाइडलाइन रेट के बजाय अपने हिसाब से जमीन की कीमत ग्राहक से वसूलते हैं और अंतर की राशि कच्चे में ली जाती है। यानी कम कीमत की जमीन का मूल्य अत्यधिक बढ़ाकर बिल्डर पैसा वसूलते हैं।

जी7 आउटरीच सत्र में बोले पीएम मोदी

भारत का '4ए' मॉडल, ऊर्जा सुरक्षा का संतुलित दृष्टिकोण

कौशल बढ़ाने के लिए एआई जरूरी

नई दिल्ली, एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी7 देशों के आउटरीच सत्र को संबोधित करते हुए ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी नवाचार और मानव केंद्रित विकास की दिशा में भारत की प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट रूप से रखा। सत्र का मुख्य विषय था- 'ऊर्जा सुरक्षा:विविधता, तकनीक और बुनियादी ढांचा ताकि बदलती दुनिया में पहुंच और वहन क्षमता सुनिश्चित की जा सके।' प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर अपने कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी द्वारा दिए गए आमंत्रण के लिए आभार व्यक्त किया और जी7 समूह को उसकी 50वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ आमंत्रणों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, जिसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सतत विकास के जरिए ही हल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और तकनीकी नवाचार के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एआई आज कौशल और नवाचार को बढ़ाने का एक प्रभावशाली माध्यम बन चुका है, लेकिन साथ ही यह ऊर्जा की खपत भी तेजी से बढ़ा रहा है। ऐसे में यह



भारत का '4ए' मॉडल

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ऊर्जा नीति का परिचय देते हुए '4ए दृष्टिकोण' पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि भारत की समावेशी और टिकाऊ विकास नीति चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है...

उपलब्धता (Availability)

पहुंच (Accessibility)

वहन क्षमता (Affordability)

स्वीकार्यता (Acceptability)

विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि भारत भले ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन उसने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले ही पूरा कर लिया है।

अनिवार्य है कि एआई आधारित प्रणालियां स्वच्छ, हरित और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों से संचालित हों।उन्होंने कहा कि भारत का तकनीकी दृष्टिकोण मानव केंद्रित है- यानी ऐसी तकनीक, जो आम नागरिकों के जीवन को आसान और बेहतर बनाए।

ट्रंप-मोदी की बात पर देश में सियासत शुरू

ट्रंप से क्या बात हुई, विपक्ष को अवगत कराने सर्वदलीय बैठक बुलाए प्रधानमंत्री: कांग्रेस

विदेश सचिव ने सब कुछ बता दिया है, अब इसमें कोई भ्रम या संदेह नहीं है: भाजपा

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, आज फोल्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाट्स हाउस से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भोजन करने का निमंत्रण मिला है। असीम मुनीर ने भी भड़काऊ बात कही थी, उसका संबंध सीधा परलेगाम में हुए आतंकी हमले से था। मैं समझता हूं कि व्हाट्स हाउस में ऐसे व्यक्ति को भोजन के लिए आमंत्रित करना हमारी कूटनीति और प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बहुत बड़ा टक्का है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 बार यह दावा किया है कि उनकी मध्यस्थता के कारण ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया गया था। आज विदेश सचिव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट तक फोन पर बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी को एक सर्वदलीय बैठक रखकर इस बातचीत से विपक्ष के नेताओं को अवगत कराना चाहिए। वे (प्रधानमंत्री मोदी) संवाद से क्यों भाग रहे हैं?

छत्तीसगढ़-आंध्रप्रदेश बॉर्डर पर 3 नक्सली लीडर ढेर

इनमें 40 लाख का इनामी गजरला भी

विजय मत, ब्यूरो जगदलपुर

छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर मोरंडाहल्ली में हुई मुठभेड़ में गेहाउडस फोर्स ने नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेबर गजरला रवि, अरुणा समेत 3 बड़े कैडर्स को मार गिराया है। गजरला 40 लाख का इनामी था। फिलहाल मुठभेड़ खत्म हो गई है। इलाके में संचिंग जारी है।

मामला आंध्रप्रदेश के अह्यूरी सीताराम जिले का है। एनकाउंटर में मारी गई अरुणा स्पेशल जोनल कमेटी मेबर श्री और नक्सली लीडर चलपति की पत्नी है। इस पर 20 लाख का इनाम था। आंध्र के अह्यूरी सीताराम जिले के एस्परी अमित बरदार ने मुठभेड़ की पुष्टि की है।



चार माह बाद शुरू होंगे विवाह मुहूर्त, तैयारियां अभी से शुरू...

देवोत्थान एकादशी के बाद नवंबर से एक बार फिर वैवाहिक आयोजनों का शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा, लेकिन परिजनों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंडप बुकिंग जून की शुरुआत से ही शुरू हो गई है। वहीं, कुंडली मिलान के लिए लगातार ज्योतिषाचार्यों से संपर्क किया जा रहा है। कई जोड़े जो एक ही कार्यालय में कार्यरत हैं, खासकर आईटी सेक्टर में, वे भी अब इस प्रक्रिया को गंभीरता से लेने लगे हैं। रिश्तों के अग्रिय को लेकर परिवार वाले कोई जोखिम नहीं लेना चाहते।

संस्थापक

श्री रामसिपाही शुक्ल

धार्मिक यात्रा में बढ़ती हवाई दुर्घटनाएं

भारत धर्म और आस्था का देश है, लेकिन यहाँ धार्मिक यात्राएं सुरक्षित नहीं हैं। जब चारधाम जैसी यात्रा भी सुरक्षित नहीं है तो दूसरे की बात छोड़िए। धार्मिक स्थलों पर आए दिन श्रद्धालुओं के मरने की घटनाएं होती रहती हैं। उत्तराखंड में आए दिन हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं सुर्खियों में हैं। मई और जून में अब तक पांच दुर्घटनाएं सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। हदसों में चालक दल के साथ 14 लोग मारे जा चुके हैं।

पवित्र चारधाम यात्रा के दौरान यह आम बात हो गई है। जून 2009 से जून 2025 तक 15 हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाएं हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबित 16 साल में इस तरह की दुर्घटनाओं में 45 लोगों की मौत हुई है। रविवार 15 जून को गौरीकुंड के पास एक हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में पायलट सहित 7 लोग मारे गए। चार धामयात्रा प्रबंधन ने इसके पूर्व हुई दुर्घटनाओं से सबक नहीं लिया। 17 मई को केदारनाथ में एम्स त्रुथिकेश की एक हेली एम्बुलेंस की इमरजेंसी लैंडिंग हुई जिसमें हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबित 12 वर्षों में केदारनाथ में कुल 14 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 33 लोगों की मौत हुई। धार्मिक यात्रा के दौरान बढ़ता जोखिम हमारी व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। नागरिक और उड्डयन मंत्रालय को इस तरह के हदसों पर गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है। निजी एविएशन कंपनियों पर नकेल कसने की जरूरत है। धार्मिक स्थलों पर बढ़ते हदसे हमारे विश्वास और आस्था पर चोट पहुँचाते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान बढ़ते हेलीकॉप्टर हदसे को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। निश्चित रूप से राज्य सरकार का यह उचित फैसला। भारत सरकार के डीजीसीए ने अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर की सभी उड़ानों पर रोक लगा दिया है। लेकिन सिर्फ रोक से काम नहीं चलेगा सम्वधित घटनाओं की जाँच होनी चाहिए। सवाल उठता है किस तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं।

नोट

सम्पादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेख-आलेख एवं विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं अतः यह जरूरी नहीं है कि विजय मत समूह उपरोक्त लेख या विचारों से सहमत हो। किसी लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार हैं।

एफएटीएफ के निशाने पर है पाक का आतंकवाद

ललित गर्ग

विश्व में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण पर नजर रखने वाली संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) ने भले ही अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं डाला है, लेकिन उसने अंततः 22 अप्रैल को पहलगाम की क्रूर आतंकवादी हमले की निंदा की है। ऐसा करते हुए एफएटीएफ ने भारत की तार्किक दलील पर ही मोहर लगायी है जो भारत की इस विषयक सफलता को द्योतक हैं। एफएटीएफ ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि 'ऐसे घटनाक्रम बिना पैसे और आतंकवादियों के समर्थकों के बीच फंडों के स्थानांतरित करने के बगैर नहीं हो सकते।' आखिरकार भारत की यह चिर-प्रतीक्षित मांग कि पाक को आतंकवाद के पोषण के लिये कटघरे में खड़ा किया जाए, इस मांग के सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का ही संकेत हैं। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद विश्व जनमत को पाकिस्तान की हकीकत बताने के जो सार्थक प्रयास किए थे, भारत के सांसदों एवं अफसरों के प्रतिनिधिमण्डल को पाक को बेनकाब करने के लिये विश्व के प्रमुख देशों में भेजा, वे फलीभूत होते नजर आ रहे हैं। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में किसी देश को तब तक निगरानी में रखा जाता है, जब तक कि वह अपनी वित्तीय प्रणाली में पड़चानी गई खामियों, त्रुटियों, विसंगतियों को ठीक नहीं कर लेता। पाकिस्तान निरंतर आतंकवाद को पोषण एवं प्रोत्साहन देने के लिये 2022 तक ग्रे लिस्ट में था, उसी वर्ष उसे ग्रे लिस्ट से हटाया गया, बावजूद पाकिस्तान ने कोई सुधार नहीं किया है और आतंकवादियों को न सिर्फ सुरक्षित पनाहगाह उपलब्ध करा रहा है, बल्कि आतंकवाद के वित्तपोषण जैसे आपराधिक कार्यों में भी खुद को शामिल करते हुए आतंकवाद की प्रयोगशाला बना हुआ है। एफएटीएफ ने फरवरी 2019 में पुलवामा आत्मघाती हमले की भी निंदा करते हुए ऐसे ही कठोर शब्दों का उपयोग किया था। लेकिन इस बार का अंतर यह है कि एफएटीएफ ने घोषणा की है कि 'राज्य प्रयोजित आतंकवाद' इसकी आगामी रिपोर्ट में आतंकवाद के वित्तपोषण मामलों की जांच का हिस्सा होगा। दरअसल, पहलगाम नरसंहार के बाद भारत लगातार पाक को फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग करता रहा है। जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय ऋणों तक पहुंच को गंभीर रूप से सीमित कर देगा।

(यह लेखक के निजी विचार हैं) –साभार

वैश्विक स्तर पर भारत के विरुद्ध पुनः गढ़े जा रहे झूठे विमर्श

प्रहलाद सबनानी

वैश्विक स्तर पर आर्थिक जगत में भारत का उदय कुछ देशों को रास नहीं आ रहा है। विकसित देशों के बीच पूरे विश्व में भारत आज सबसे तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली आदि देशों से आगे निकलते हुए भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और शीघ्र ही लगभग एक वर्ष के बाद जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के आसार भी अब स्पष्ट-दिखाई दे रहे हैं। भारत एक और अतिआधुनिक तकनीक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डाटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में पूरे विश्व का नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है तो दूसरी ओर वित्तीय क्षेत्र में ऑनलाइन व्यवहारों के मामले में भी भारत आज कई देशों का मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर भारत आज लगभग प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते हुए विश्व के अन्य देशों पर अपनी निर्भरता को कम करता जा रहा है। भारत के विकास की यह गति एवं राह कुछ देशों को बिलकुल उचित नहीं लग रही है एवं वे वैमनस्य का भाव पालते हुए भारत के विरुद्ध एक बार पुनः कुछ झूठे विमर्श गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।

भारत में किस प्रकार का आर्थिक विकास हो रहा है जिससे भारतीय नागरिकों की आय तो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है, जिस तेजी से भारत का आर्थिक विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। आंकड़ों का उचित तरीके से विश्लेषण न करते हुए भारत के संदर्भ में गलत जानकारी देने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी भी मामले में तुलना दो आमों के बीच ही सम्भव है आम एवं संतरे के बीच तुलना कैसे सम्भव है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, जबकि बांग्लादेश की जनसंख्या केवल 17 करोड़ से कुछ ही अधिक है। भारत एक विशाल देश है जिसमें 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या आज भी गावों में निवास करती है। भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बांग्लादेश, भारत के सामने एक पिढ़ी सा देश है। यदि तुलना करनी ही हो तो भारत की तुलना चीन से की जा सकती है। इसी प्रकार, बांग्लादेश की तुलना स्विट्जरलैंड, नोदरलैण्ड, स्वीडन आदि जैसे छोटे देशों से की जा सकती है। स्विट्जरलैंड में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 99,564 अमेरिकी डॉलर; नोदरलैण्ड में 64,572 अमेरिकी डॉलर एवं स्वीडन में 55,516 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति है। ब्रिटेन ने जब भारत में अपनी सत्ता को छोड़ा था अर्थात भारत ने वर्ष 1947 में जब राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त की थी तब भारत की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी, परंतु आज केवल 4 से 4.5 प्रतिशत भारतीय ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। जबकि,

बेटियाँ आगे बढ़ रही, पर मंच अब भी खाली

सोनम लववशी

यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2024 जब यह कहती है कि लड़कियों की शैक्षणिक प्रगति वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय रही है, तो यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, एक उम्मीद का सिरा है। भारत में भी यह बदलाव साफ नजर आता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद से प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक लड़कियों की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है। उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी अब 49 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है। यह एक ऐसा तथ्य है जो न केवल भारत के भविष्य की दिशा तय करता है, बल्कि सामाजिक संरचना में बदलाव के संकेत भी देता है, किंतु इसी उजाले के साथ एक लंबी छाया खिंची है। जब बात नेतृत्व की होती है, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, कॉरपोरेट की ऊँचाइयों, या तकनीकी दुनिया के निर्णायक मोर्चे, महिलाएं वहाँ बहुत पीछे खड़ी नजर आती हैं। केवल 7.2 प्रतिशत भारतीय कंपनियों में महिलाएं सीईओ पद पर हैं। संसद में उनकी भागीदारी 14 प्रतिशत से भी कम है। वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा थोड़ा ही बेहतर है। विश्व बैंक की साल 2024 की रिपोर्ट की माने तो, विश्वभर में शीर्ष नेतृत्वकारी पदों में केवल 10 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं की है। यह आंकड़े न सिर्फ स्थिति की गंभीरता बताता हैं, ये सवाल भी उठता हैं कि आखिर क्यों शिक्षा में आगे निकल चुकी महिलाएं नेतृत्व के पायदान पर पिछड़ जाती हैं?

पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक अपेक्षाएं, और कार्यस्थलों पर मौजूद लैंगिक भेदभावी की संरचनाएं मिलकर एक ऐसा वातावरण निर्मित करती हैं, जहाँ महिलाएं नेतृत्व के अवसरों से वंचित रह जाती हैं। अवसर मिलने पर भी उन्हें दुगना संघर्ष करना होता है। राजनीति जैसे क्षेत्र में तो यह और भी कठिन हो जाता है, जहाँ जोखिम, सार्वजनिक आलोचना, और कभी-कभी हिंसा तक का सामना करना पड़ता है। विश्व आर्थिक मंच की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि कार्यबल में वैश्विक रूप से महिलाओं की भागीदारी 42 प्रतिशत है, लेकिन वरिष्ठ नेतृत्व में यह संख्या घटकर केवल 31.7 प्रतिशत रह जाती है। इसी प्रकार, स्टीम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) क्षेत्रों में महिलाओं की वैश्विक भागीदारी मात्र 28.2 प्रतिशत है। इसका अर्थ यह है कि महिलाएं केवल शिक्षा तक सीमित नहीं, ज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी अनदेखी का शिकार हैं।

वेतन असमानता भी एक बड़ी बाधा है। विश्व बैंक की वीमेन, बिजनेस एंड द लॉ- 2024 की रिपोर्ट बताती है कि महिलाएं औसतन पुरुषों की तुलना में 2.4 घंटे अधिक अवैतनिक देखभाल कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त, 98 देशों में समान वेतन के कानून तो हैं, लेकिन केवल 35 देशों में ही ऐसे कानूनों के प्रवर्तन और पारदर्शिता के लिए मजबूत ढांचा है। इसका सीधा प्रभाव महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और नेतृत्वकारी भूमिका पर पड़ता है। इन सबके बावजूद, तस्वीर पूरी तरह धुंधली नहीं है।

शब्द पहेली - 8402

	1		2		3		
							5
				4			
6			7		8		
	9		10			11	
12			13			14	
15					16		17
			18			19	
20					21		
				22			

बाएँ से दाएँ

1.वटवृक्ष, बट-4

4.मितव्यय,बचत-4

6.-सनाप, बेतुकी बकवास-3

8.भाड़ा-3

9.मृत्यु होना-3

11.खुशी, सहमत-2

13.अक्लमंद, समझ वाला-5

15.बलिदान, उत्सर्ग-2

16.जबान, जीभ, जिह्वा-3

18.गिरोह, मंडली, समूह-3

19.अपनापन, प्रेम, स्नेह-3

20.फूलना-फलना-4

22.अभिलाषा, आकांक्षा, हसरत-4

ऊपर से नीचे

1.कलंकित, निंदित, लांछित-3

2.दुख, शोक, अफसोस-2

3.खात्मा, समाप्ति, बर्बाद-3

4.मकान आदि भाड़े पर लेने वाला-5

5.संस्कृति, सभ्यता-4

7.स्पर्श, छूना-3

10.ख्याति अर्जित करना (मु.-2,3)

12.वह आरोप जो किसी आरोप के जवाब में किया जाय-4

14.परंपरा, नियम, चाल -3

17.ख्याति, जाना-पहचाना-3

18.माला आदि फैरना-3

21.जेबकतरा, ठग, डाकू-2

शब्द पहेली -8401 का हल

र	म	णी	य		ब	र	स	
वा	म	की		ह		म	त	
य		अ	न	ब	न		म	
त	म	स	री		स	र	स	
		बा	ज		पा	रो		
स	ली	ब	मी		व	ज	ह	
ली			म	न	ह	र	रा	
का	म		न		र	श	र	
	द	म	न		म	हा	व	त

Jagrutidaur.com, Bangalore

बांग्लादेश में लगभग 19 प्रतिशत नागरिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आकार आज 4.19 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है जबकि बांग्लादेश के सकल घरेलू उत्पाद का आकार केवल लगभग 46,700 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। सकल घरेलू उत्पाद को देश की कुल जनसंख्या से बांट कर ही प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े को प्राप्त किया जा सकता है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक है जबकि बांग्लादेश की जनसंख्या मात्र 17 करोड़ है। इससे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का आंकड़ा बांग्लादेश की तुलना में कुछ कम हो जाता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों के दौरान बहुत संतुलित विकास हुआ है। भारत में न केवल धनाडयों की संख्या में अपार वृद्धि दर्ज हुई है बल्कि गरीबी उन्मूलन पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है जिससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या में भी अतुलनीय कमी दर्ज हुई है।

बांग्लादेश की तुलना में भारत एक विशाल देश है एवं भारत के कई राज्यों यथा महाराष्ट्र, गुजरात एवं तमिलनाडु आदि का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद बांग्लादेश की तुलना में दुगने से तिगुने आकार का है। इसी प्रकार, भारत के राज्य अभी भी कुछ पिछड़े राज्यों की श्रेणी में शामिल है, जैसे, बिहार, झारखंड आदि। परंतु किसी भी देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का औसत निकालते समय देश के समस्त राज्यों के आंकड़ों को शामिल करना होता है।

इस कारण से भी भारत में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का औसत कुछ कम हो जाता है।

हाल ही के समय में एक और कुतर्क दिया जा रहा है कि भारत में तेज गति से हो रही आर्थिक प्रगति के बीच भी बच्चों की जन्म-मृत्यु की दर अफ्रीकी देशों के समान बनी हुई है। इस प्रकार का झूठा विमर्श गढ़ते समय संभवतः वास्तविक स्थिति की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया है। रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया की एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 1,000 शिशुओं के जन्म के बीच शिशुओं की जन्म-मृत्यु दर केवल 26 है। जबकि अफ्रीकी देशों यथा नाईजीरिया में 67, कांगो में 62 एवं इथियोपिया में 34 है। इन सभी अफ्रीकी देशों की तुलना में भारत में शिशुओं की जन्म-मृत्यु दर कम है। अतः भारत अब अफ्रीकी देशों से इस मामले में बहुत आगे निकल आया है। हां, इस संदर्भ में भारत की तुलना यदि विकसित देशों से की जाएगी यथा अमेरिका में 5 एवं जापान में 2, तब जरूर भारत में इस स्थिति को अभी और अधिक सुधारने की आवश्यकता है, जिसके लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार बहुत तेज गति से किया जा रहा है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)– साभार

बदलाव की किरणें मौजूद हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के बाद से स्थानीय स्तर पर नेतृत्व में उनकी भागीदारी में सुधार देखा गया है। यह दिखाता है कि जब अवसर और संरचना दोनों सकारात्मक रूप में मिलते हैं, तो महिलाएं नेतृत्व में भी उत्कृष्टता दिखा सकती हैं। वैश्विक स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व बैंक की जेंडर स्ट्रेटेजी 2024-2030 का लक्ष्य है कि 2030 तक 300 मिलियन महिलाओं को डिजिटल कनेक्टिविटी, 250 मिलियन को सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क और 80 मिलियन महिला-नेतृत्व वाले व्यवसायों को वित्तीय समर्थन दिया जाए। ये योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने के प्रयास नहीं, एक समावेशी भविष्य की नींव हैं। सवाल यह है कि इस नींव पर हम कैसे निर्माण करेंगे?

सबसे पहले तो जरूरी है कि समाज में गहराई तक समाई लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ा जाए। यह काम केवल पाठ्यक्रम बदलने या पोस्टर लगाने से नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि बचपन से ही लड़के और लड़कियों दोनों को समानता, नेतृत्व और सह-अस्तित्व के मूल्यों की शिक्षा दी जाए।

कार्यस्थलों पर भी व्यापक बदलाव जरूरी है। मातृत्व अवकाश, लचीली कार्य व्यवस्था, यौन उत्पीड़न के मामलों में सख्त कार्यवाही, और महिलाओं की पदोन्नति के लिए पारदर्शी बढाने के लिए सिर्फ आरक्षण पर्याप्त नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि आरक्षण सांकेतिक न रहे, बल्कि उसके माध्यम से वास्तविक और प्रभावी नेतृत्व उभर कर सामने आए। इसके लिए उच्च प्रशिक्षण, संसाधन और एक सुरक्षित सार्वजनिक वातावरण प्रदान करना होगा। समाज को यह समझने की आवश्यकता है कि महिलाओं का नेतृत्व महिलाओं के लिए नहीं, पूरे समाज के विकास के लिए जरूरी है। जिन क्षेत्रों में महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिला है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया अधिक समावेशी, दीर्घकालिक और मानवीय दृष्टिकोण वाली रही है।

महिलाओं की शिक्षा में हो रही प्रगति सराहनीय है, लेकिन यह तब तक अधूरी है जब तक वह नेतृत्व की ऊँचाइयों तक न पहुँचे। जब एक शिक्षित लड़की केवल एक नौकरी ही नहीं, बल्कि एक संस्था, एक आंदोलन, या एक नीति का नेतृत्व करती है, तभी हम कह सकते हैं कि शिक्षा ने अपना उद्देश्य पूरा किया है। समाज को यह स्वीकारना होगा कि नेतृत्व कोई जन्मगत विशेषाधिकार नहीं, अर्जित किया गया दायित्व है और जब तक महिलाओं को इस दायित्व को निभाने का पूरा अवसर नहीं मिलेगा, तब तक हम एक सशक्त, समावेशी और प्रगतिशील राष्ट्र नहीं बन सकते। अतः यह समय केवल आंकड़ों की तालिका सजाने का नहीं, उन आंकड़ों को जीने और बदलने का है। यह समय है कि हम लड़कियों की शिक्षा से आगे बढ़कर उन्हें नेतृत्व के मंच तक पहुँचाएं। क्योंकि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो समाज भी आगे बढ़ता है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)– साभार

दैनिक पंचांग

19 जून 2025 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

गुरुवार 2025 वर्ष का 170 वा दिन
दिशाशुल दक्षिण ऋतु वर्षा।
विक्रम संवत् 2082 शक संवत् 1947
मास आषाढ़ (दक्षिण भारत में ज्येष्ठ)
पक्ष कृष्ण तिथि अष्टमी 11.56 बजे को समाप्त। चक्षुर उत्तराभाद्रपदा 23.17 बजे को समाप्त। योग आयुष्मान 05.24 बजे तदनन्तर सीमांय 02.46 बजे रात्र को समाप्त। करण कौलव 11.56 बजे तदनन्तर तैत्तिल 22.56 बजे को समाप्त। चन्द्रायु 22.9 घण्टे रवि क्रांति उत्तर 23° 25' सूर्य उत्तरायन कलि अहरण 1872380 जूलियन दिन 2460845.5 कलियुग संवत् 5125 कल्पावर्ध संवत् 1972949123 सृष्टि गृहारंभ संवत् 1955885123 वीरनिर्वाण संवत् 2551 हिजरी सन् 1446 महीना जिल्हेज तारीख 22

दिन का चौघड़िया

शुभ 05.54 से 07.22 बजे तक	रोग 07.22 से 08.51 बजे तक
उद्देग 08.51 से 10.19 बजे तक	चर 10.19 से 11.47 बजे तक
लाभ 11.47 से 01.15 बजे तक	अमृत 01.15 से 02.43 बजे तक
काल 02.43 से 04.11 बजे तक	शुभ 04.11 से 05.40 बजे तक

रात का चौघड़िया

अमृत 05.40 से 07.11 बजे तक	रोग 07.11 से 08.43 बजे तक
लाभ 08.43 से 10.15 बजे तक	लाभ 10.15 से 11.47 बजे तक
उद्देग 11.47 से 01.19 बजे तक	शुभ 01.19 से 02.51 बजे तक
अमृत 02.51 से 04.23 बजे तक	शुभ 04.23 से 05.55 बजे तक

ज्योडिया शुभाशुभ- शुभमशुभ शुभ, अमृत व लाभ, मध्यम चर, अशुभ उद्देग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■ Jagrutidaur.com, Bangalore

कोशिका में उसे समझाने की कोशिश की तो गुरुसे में आकर आंगन में रखे लकड़ी के टुकड़े को सिर पर दे मांग, जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गईं। परिजनों ने तत्काल उसे बसना के शासकीय अस्पताल पहुँचाया, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में बसना थानेदार नरेंद्र राठौड़ ने बताया कि आवेश में आकर भाई ने बहन पर प्राण घातक हमला किया। घायल बहन को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मृतका की बहन की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी भाई सलीम उर्फ गोलू जौहरि को खिलाफ फामाल दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

नबे दिह्लो। यात्रा बुकिंग मंच मेकमाईट्रिप का कहना है : 'कि बह शेयर ओवर परिवर्तनीय बॉण्ड की बिक्री के जरिये 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की पूंजी जुटाने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी शेयर बाजार में नैस्डैक के दो की गई संचालन के अनुसार इन जहाँ गई राशि का दोबई कंपनी में स्थित ट्रिप डॉट कॉम समूह की हिस्सेदारी को उल्लेखनीय रूप से कम करना है। नैस्डैक में सूचीबद्ध कंपनी ने पेपकश से 'हाल की गई आय के साथ-साथ परिवर्तनीय बॉण्ड की पेशकश से दिहलें राशि का इस्तेमाल कंपनी द्वारा पहले ऑर्थोग्रैफिस्ट अपने 'क्लास बी' शेयर के एक हिस्से को पुनर्खरीद करने के लिए करने की योजना बनाई है। सामान्यतः क्लास बी शेयर में सामान्य शेयरों के संयोजन में अधिकार बने प्रथमिकताएं होती हैं, सिवाय इसके कि इस श्रेणी के शेयर को नियंत्रित करने वाली निर्गम शर्तों को विशेष रूप से निर्धारित किया गया हो।

न्यूज विंडो

छा हाईकोर्ट में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर लगा पूर्ण प्रतिबंध



बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट परिसर में अब मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लेकर जाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनोप कुमार ठाकुर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, न्यायालय कक्ष में उपस्थित रहने वाले पक्षकारों और वार्दियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (भले ही स्विच ऑफ मोड में हो) अंदर न ले जाएं।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोर्ट की कार्यवाही के किसी भी भाग की रिकॉर्डिंग सख्त रूप से प्रतिबंधित है। यदि कोई व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग) नियम, 2022 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि पहले से ही कोर्ट रूम में मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखने की हिदायत थी, ताकि कोर्ट की कार्यवाही बाधित न हो। लेकिन हाल के दिनों में कुछ मामलों में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आई हैं, जिसके चलते यह सख्त निर्णय लिया गया है। बताया गया है कि यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर जारी किया गया है।

कुआगोंदी व्यपवर्तन की नहर के कार्यों के लिए 2.93 करोड़ स्वीकृत



रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा बालोद जिले के विकासखण्ड डोंडीलोहारा की कुआगोंदी व्यपवर्तन नहर के लाईनिंग एवं अन्य कार्यों के लिए 2 करोड़ 93 लाख 83 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर यहां पर रूपांकित सिंचाई 276 हेक्टेयर में 165 हेक्टेयर की सिंचाई की पूर्ति सहित पूरे रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा हो जाएगी। जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से योजना के कार्यों को पूर्ण कराने मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रशासकीय स्वीकृत जारी की गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की छात्रवृत्ति योजना से 38 हजार से अधिक मेधावी छात्र-छात्राएं लाभान्वित

वन मंत्री ने कहा तेन्दूपत्ता संग्राहकों के बच्चों को शिक्षा में मदद देने की महत्वपूर्ण पहल



विजय मत, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना ने वनवासी क्षेत्रों में शिक्षा की अलख जगाने की दिशा में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। वर्ष 2013-14 में प्रारंभ की गई छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना की परिकल्पना के

समय यह अनुमान था कि लगभग 100-100 मेधावी छात्र-छात्राएं इससे लाभान्वित होंगे, लेकिन बीते वर्षों में योजना की व्यापकता और प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2019-2020 से अब तक कुल 38,114 छात्र-छात्राओं को इस योजना के माध्यम से 41.79 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति राशि ऑनलाइन माध्यम से वितरित की गई है। छात्रवृत्ति योजना में कुल चार प्रमुख घटक शामिल हैं जिसके तहत मेधावी छात्र-छात्राओं के

लिए छात्रवृत्ति, प्रतिभाशाली बच्चों हेतु शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति, व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति तथा गैर-व्यावसायिक स्नातक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति शामिल है। इन सभी श्रेणियों के अंतर्गत 2,500 से 25,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाती है, जिससे छात्रों को अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने में आर्थिक संबल मिलता है।

वन मंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा संचालित यह योजना न केवल आर्थिक रूप से पिछड़े वनवासी क्षेत्रों के छात्रों को शिक्षा से जोड़ने में मदद कर रही है, बल्कि उनके भविष्य को भी सशक्त बना रही है। यह पहल राज्य सरकार के शिक्षित और सशक्त छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक सशक्त कदम है।

इंडिगो फ्लाइट का गेट हुआ लॉक रायपुर एयरपोर्ट में यात्री हुए परेशान



विजयमत, रायपुर

अहमदाबाद घटना के बाद से हवाई उड़ान को लेकर इन दिनों यात्री कुछ संशय के साथ सफर कर रहे हैं। आज एक घटना से फिर यात्री हड़बड़ा गए।मामला रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट का है,दिल्ली से रायपुर पहुंची इंडिगो फ्लाइट 2.25 पर लैंड तो हो गई,लेकिन फ्लाइट का गेट लॉक हो गया। कुछ देर तक गेट लॉक रहा। इससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक इस फ्लाइट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक

सरकार नहीं चाहती किसान, धान की पूरी पैदावार लें : भूपेश बघेल

विजय मत, रायपुर



पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुये कहा कि सरकार नहीं चाहती किसान, धान की पूरी पैदावार ले सके। इसीलिये पूरे प्रदेश में उर्वरकों विशेषकर डीएपी, एनपीके का संकट पैदा किया जा रहा, किसानों को बीज नहीं उपलब्ध करवाया जा रहा, सरकार की मंशा धान के रकबे को कम करना है ताकि समर्थन मूल्य पर कम धान खरीदना पड़े। यहां की जलवायु और मिट्टी धान के फसल के अनुकूल है। खरीफ का धान हमारे किसानों की प्रमुख उपज है। इसमें व्यवधान राज्य के किसानों के लिये घातक है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार दूसरी

फसलों को बढ़ावा दे, लेकिन किसानों का नुकसान कर के ऐसा किया जायेगा तो ठीक नहीं है। किसानों को नुकसान पहुंचा कर नहीं लाभ देकर दूसरी फसलों की ओर प्रेरित किया जाये। हमारी सरकार थी तब हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान के किसानों को 90000 रु. प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देते थे। दूसरे फसल लेने वालों को 100000 रु. प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देते थे। किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिये। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

ने कहा कि मानसून की दस्तक शुरू हो गयी है। खरीफ की बुवाई खाद और बीज की कमी के कारण प्रभावित हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसानों की समस्या का कोई ख्याल नहीं है। मानसून बस्तर आ चुका है, पूरे प्रदेश में खरीफ फसल के बुवाई की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है, खुरी वाले किसान प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं, लेकिन प्रदेश में खाद और बीज की समुचित व्यवस्था यह सरकार नहीं कर पाई है। प्रदेश के ज्यादातर सोसाइटी में किसानों को डीएपी की कमी से जूझना पड़ रहा है, ज्यादातर स्थानों पर बोनी और थरहा के लिए बीज भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते किसान परेशान हैं।

नशे में धुत हिस्ट्रीशीटर ने कार से बाइक सवारों को मारी ठोकर

युवती समेत 4 की मौत, पुलिस ने किया गिरफ्तार

विजय मत, रायपुर

बीते रविवार की रात को पेण्ड्रा थाना क्षेत्र के सेवरा गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों और एक युवती की मौत हो गई। हादसे को अंजाम देने वाला आरोपी स्नेहिल गुप्ता शराब के नशे में धुत था और अपनी तेज़ रफ्तार ब्रेज़ा कार से सामने से आ रही दो मोटरसाइकिलों को जोरदार ठोकर मार दी। इस हादसे के बाद उसने मृतकों के परिजनों से मौके पर

बदसलूकी भी की और धौंस जमाते हुए कहा कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी स्नेहिल गुप्ता पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) समेत कई गंभीर गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि 25 वर्षीय स्नेहिल गुप्ता मरवाही का रहने वाला है।